क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किये गये खंडों की संख्या
20	तमिलनाडु	56
21	त्रिपुरा	18
22	उत्तर प्रदेश	145
23	पश्चिम बंगाल	128
24	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
25	दादर व नगर हवेली	1
26	दमन व दीव	1
27	लक्षद्वीप	5
	योग :	1755

Assistance by Banks under IRDP

3249. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of beneficiaries assisted by the banks under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) during the last three years, year-wise;

(b) the percentage of the beneficiaries who belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the I.R.D.P. during the same period;

(c) the percentage of advances of public Sector banks of their net bank credit to weaker sections during the same period;

(d) whether it is a fact that there has been large scale misutilisation and default of rural banks credit during the same period; and

(e) if so, the details thereof and the reasons therefor and what corrective steps Government have taken/propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Information is given in the Statement, (*See below*).

(c) As per information in the R.B.I. Reports, the percentage of advances of Public Sector banks of their net bank credit to weaker sections during the last three years was 9.7% (1990-91), 9.7% (1991-92) and 8.9 per cent (1992-93).

(d) and (e) The evaluation study conducted by Government/ Reserve Bank of India does not indicate large scale misutilisation of funds. The recovery performance was however not

satisfactory. The major reasons for poor recovery are reported to be inadequate income generation, costly maintenance, high input prices defective assets and unexpected natural calamities, diversion of income for meeting more urgent consumption needs etc. The Government has taken adequate care to guard against the misuse of IRDP funds by calling regular reports regarding action taken on cases of corruption/misutilisation/malpractices involving IRDP funds. The Government of India has also advised the States to assist banking sector in the recovery of the loans under I.R.D.P.

Statement

Families assisted under Integrated Rural Development Programme during the last three years

Year	Total families assisted (No. in lakhs)	% of SC/ST families assisted
1990-91	28.98	49.90
1991-92	25.37	51.08
1992-93	20.69	51.41

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों की कमी

3250. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पहली मार्च, 1991 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 206 लाख आवासीय मकानों की कमी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण के अनुसार बढ़ती आबादी के कारण प्रति वर्ष अनुमानतः 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों की आवश्यकता होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की इस समस्या को हल करने हेतु कोई योजना तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आवासीय मकान बनाये जाने का लक्ष्य है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आवासीय मकानों की कमी होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास की योजनाएं अलग-अलग राज्य सरकारों में अलग-अलग हैं । उनके प्रयासों में सहायता देने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों के लिए चल रहे आवास कार्यक्रमों के [illegible] संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने का एक योजना तैयार की जा रही । इस योजना के ब्यौरे इसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

(ङ) ऐसी आशा है कि इस योजना से आवास की कमी में और गिरावट आएगी ।